नवल टाइम्स

RNI No. UTTHIN/2012/42590

भारत सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

वर्ष : 14 अंकः 16 हिन्दी साप्ताहिक हरिद्वार, बृहस्पतिवार 08 मई 2025 मूल्यः 1 रूपया पृष्ठः 4

चारधाम यात्रा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाएः मुख्यमंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद सीएम धामी ने ली उच्चस्तरीय बैठक, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील

देहरादून (नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतेजाम किये जाएं। उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे राज्य के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए जाएं, सीमांत क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री प्रतिभाग कर रहे हैं, इसलिए यात्रा मार्ग सहित चारों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान हैं, इन संस्थानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जिला और तहसील स्तर पर खाद्यान सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखी जाए। अस्पतालों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलर्ट रखा जाए। सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध किया जाय। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा दल और स्वयंसेवी संस्थाओं को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को भी सही सूचनाओं के साथ सतर्क किया जाए, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि जन सामान्य के पास हर तरह से सही और प्रमाणित सूचनाएं ही पहुंचे, ताकि वो अफवाह से दूर रह सकें। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए, कार्मिकों के अवकाश मंजूर न किए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शासन प्रशासन हर तरह से मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव शैलेश बगोली, वीके सुमन शामिल हुए।

प्रेस क्लब में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

मेदांता अस्पताल के चिकित्सकों ने 108 पत्रकारों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की

हरिद्वार (नवल टाइम्स)। प्रेस क्लब में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब सभागार में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में मेदांता हॉस्पिटल नोयडा ग्रुप की चिकित्सा टीम ने पत्रकारों एवं उनके परिजनों की स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया। चिकित्सा जांच शिविर का उद्घाटन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह, एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा, प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी एवं महामंत्री दीपक मिश्रा ने फीता काटकर किया।

शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों फिजिशियन डा.सैफ रहमान, डा.रमन यादव, डा. अनूप नेगी, डा. गुंजन, डा. दीक्षा ने 108 पत्रकारों व उनके पजिरनों की बीपी, शुगर, बीएमडी, ईसीजी, पीएफटी आदि की जांच की।

एचआरडीए के सचिव मनीष सिंह ने कहा कि भागदौड़ वाले इस जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। छोटी से छोटी बीमारी का इलाज समय रहते किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविर लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने कहा कि पत्रकार पुलिस एवं विभिन्न क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे लोगों को स्वास्थ्य जांच अवश्य करानी चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया जा सकता है। चिकित्सा शिविर अवश्य ही लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पुलिस विभाग द्वारा भी जवानों की स्वास्थ्य जांच के लिए समय-समय पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी एवं महामंत्री दीपक मिश्रा ने कहा कि प्रेस क्लब के माध्यम से सकरात्मक पत्रकरिता के साथ समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन भी किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर के आयोजन का उद्देश्य पत्रकारों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से पत्रकार 24 घंटे समाज हित में योगदान देते हैं। ऐसे में उनका शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहना जरूरी है। प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेदांता व प्रेस क्लब के बीच एमओयू किए जाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार शिवशंकर जायसवाल, आदेश त्यागी, संजय आर्य, रजनीकांत शुक्ल ने कहा कि शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो स्वास्थ्य जांच जरूरी करानी चाहिए। स्वास्थ्य जांच शिविर के संयोजक डा. शिवा अग्रवाल ने सभी अतिथियों और चिकित्सकों का आभार जताया।

चिकित्सा शिविर के समापन पर श्रीगंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने पत्रकारों को गंगाजली एवं प्रसाद भेंट किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी एवं महामंत्री दीपक मिश्रा ने एचआरडीए के सचिव मनीष सिंह व एसपी क्राईम जितेंद्र मेहरा को स्मृति चिन्ह, गंगाजली भेंटकर व पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मेदांता नोएडा ग्रुप के मैनेजर अनूप नेगी व नितिन शर्मा, जिला सूचना अधिकारी नदीम अहमद, मनोज गौतम तथा अविक्षित रमन, बृजेंद्र हर्ष, बालकृष्ण शास्त्री, राजेश शर्मा, आदेश त्यागी, कुमकुम शर्मा, डा. शिवा अग्रवाल, डा. प्रदीप जोशी लवकुमार शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, श्रवण झा, संजय आर्य, नाथीराम सैनी, विकास चौहान, मुदित अग्रवाल, महावीर नेगी, महेश पारीख, दया शंकर वर्मा, अमित शर्मा, ललितेंद्र नाथ, सुनील पाल, शिव शंकर जायसवाल, राजकुमार आदि पत्रकार मौजूद रहे।

प्रदेश में नागरिक सुरक्षा पूर्वाभ्यास के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने ली बैठक

देहरादून (नवल टाइम्स)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में नागरिक सुरक्षा पूर्वाभ्यास के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि यह पूर्वाभ्यास गतिविधियां/मॉक ड्रिल प्रदेशभर में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पूर्वाभ्यास आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में अत्यधिक सहायक होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इन पूर्वाभ्यास गतिविधियों से आमजन में किसी प्रकार का पैनिक न हो इसके लिए जनता से लगातार संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिक को इन मॉक ड्रिल और उसके लाभ से अवगत कराया जाए। आपातकालीन परिस्थितियों में सभी विभागों द्वारा क्या-क्या गतिविधियां और कार्यवाही की जानी है, उसके लिए सभी विभागाध्यक्षों द्वारा अपने स्तर से तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यह एक पूर्वाभ्यास कार्यक्रम है, जिससे राज्य के प्रत्येक नागरिक को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रति प्रदेश के नागरिकों को जागरूक किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में पूर्वाभ्यास गतिविधियां/मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन एवं विपरीत परिस्थितियों में आमजन को क्या-क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

उन्होंने विद्यालय एवं अस्पतालों में आपदा से बचाव हेतु जागरूक किए जाने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव कहा कि पूर्वाभ्यास के साथ ही स्थायी तौर पर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ठोस प्लान तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय नागरिक सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जाए। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाए।

सम्पादकीय

बदलती युद्ध की प्रकृति

दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। आज की दुनिया में जब एक ओर देशों के बीच खुले युद्ध की घटनाएं घट रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक नए प्रकार का युद्ध भी सामने आ रहा है, जो चुपचाप, बिना गोलीबारी के लड़ा जाता है। लेकिन यह पारंपरिक युद्ध जितना ही खतरनाक है। इसे 'छाया युद्ध' कहा जा सकता है और इसमें सेमीकंडक्टर, साइबर हमले, झूठी खबरें, आर्थिक दबाव और डिजिटल जासूसी प्रमुख हथियार बन चुके हैं। भारत जैसे देश के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह इस बदलती युद्ध-प्रकृति को समझे और इसके लिए खुद को तैयार करे। पहले युद्धों में सेनाएं मैदान में उतरती थीं, टैंक चलते थे और मिसाइलें दागी जाती थीं। लेकिन आज का युद्ध इस तरह के हथियारों के बिना भी लड़ा जा सकता है। अब यह युद्ध कंप्यूटर कोड, चिप्स, इंटरनेट नेटवर्क और डेटा के जरिए हो रहा है। इन सभी के बीच एक क्षेत्र है जिसे धूसर क्षेत्र या ग्रे जोन कहा जाता है। यह वह जगह है, जहां न तो खुला युद्ध होता है और न ही पूर्ण शांति होती। यहां देश एक-दूसरे को परेशान करते हैं, लेकिन इस तरह कि कोई उन्हें सीधे तौर पर दोषी न ठहरा सके। इस धूसर क्षेत्र में साइबर हमले, अफवाहें फैलाना, मीडिया को प्रभावित करना, राजनीतिक हस्तक्षेप और आर्थिक दबाव जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं। यह सब कुछ इस हद तक ही किया जाता है कि सामने वाला देश सैन्य कार्रवाई करने से हिचकिचाए। अब युद्ध सेमीकंडक्टर यानी माइक्रोचिप्स और डिजिटल तकनीक से लड़े जाएंगे। हाल ही एक अमरीकी सीनेटर ने कहा था कि अगला बड़ा युद्ध सेमीकंडक्टर्स के लिए लड़ा जाएगा। यह कथन महज चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो दिन-ब-दिन सामने आ रही है। दुनिया अब डेटा, सूचना और प्रोसेसिंग पावर के लिए संघर्ष कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित प्रणालियां अब युद्ध के नए मोर्चे बन गए हैं। इस तरह दोनों देशों के बीच एक तरह का तकनीकी शीत युद्ध शुरू हो गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सेमीकंडक्टर अब केवल व्यापारिक उत्पाद नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक हथियार बन गए हैं। दुनियाभर में रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब यह खर्च सिर्फ सेना पर नहीं, बल्कि क्वांटम सिस्टम, एआइ और साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों पर भी किया जा रहा है। भारत एक तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जहां 1.3 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। आधार, यूपीआइ, डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल सेवाओं के जरिए भारत ने एक मजबूत डिजिटल ढांचा तैयार किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, हम अब भी सेमीकंडक्टर और कुछ महत्त्वपूर्ण तकनीकों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं। 2023-24 में भारत ने लगभग 90 अरब डॉलर मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात किया, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत से अधिक थी। हमारी सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर सेवाएं भी अक्सर उन हार्डवेयर पर चलती हैं, जो विदेशी हैं और असुरक्षित हो सकते हैं। यह एक बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। अंत में भारत को नीति निर्माण, पूंजी निवेश, अनुसंधान और उत्पादन के हर स्तर पर सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनना चाहिए, न कि केवल उद्योग या आइटी मंत्रालय का। दुनिया में जब भी नई तकनीक आती है तो वह सिर्फ विकास का साधन नहीं होती, वह शक्ति का साधन भी बन जाती है। सेमीकंडक्टर, साइबर स्पेस, डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब वही साधन हैं। भारत के पास प्रतिभा है, इच्छाशक्ति है, लेकिन अब जरूरत है एक स्पष्ट रणनीति और मिशन की।

पाकिस्तान के आतंकियों को भारतीय सेना का करारा जवाब

7 मई की रात भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे आतंकी अड्डों पर एक सुनियोजित और व्यापक हमला किया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन वीर जवानों की शहादत का जवाब था, जिनकी जान आतंकी हमलों में गई थी। यह जवाब उन साजिशों के खिलाफ भी था, जो भारत की अखंडता और शांति के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से लगातार रची जा रही थीं। इस संयुक्त ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 9 से अधिक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, लगभग 700 से 900 आतंकियों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो इन शिविरों में छिपे हुये थे। आतंकी संगठनों के लिए ऑपरेशन सिंदूर स्पष्ट संदेश है, भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब निर्णायक तरीके से देगा। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना भी प्रतीकात्मक है। यह उन शहीदों की विधवाओं के माथे से मिटे सिंदूर का जवाब है। इस नाम के माध्यम से भारत ने यह दिखा दिया है, भारत अपने सैनिकों और नागरिकों की शहादत को न तो भूलेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा। आज देशभर में लोग जय हिंद और भारतीय सेना अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। यह समय सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि अत्यंत सतर्कता का भी है। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान भ्रष्टाचार, गरीबी, भूख और आतंकवाद से ग्रस्त है।

जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है

किशन भावनानीं

भारत प्राकृतिक संसाधनों में सर्वगुण संपन्न वाला एक ऐसा अनोखा देश है जहां सृष्टि की की अपार रहमत बरसी है,बस जरूरत है हमारे अपार समृद्ध जनसांख्यिकीय तंत्र को अपनी विश्व प्रतिष्ठित बौद्धिक क्षमता, कौशलता का उपयोग कर इन्हें विलुप्तता या नष्ट होने से बचाएं, क्योंकि जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए विपत्तियों की स्थिति पैदा कर रहे हैं।आज हमें सबसे अधिक संरक्षरण की जरूरत जल, भूमि और मिट्टी की है और उस भूमि, मिट्टी में हमारी कृषि होती है इसलिए श्लोकों में भी आया है।जीव जीवनम् कृषि अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है क्योंकि मानव का भाग्य और भविष्य जल, भूमि, मिट्टी इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर निर्भर है।

साथियों बात अगर हम भारत में भूमि की करें तो हम उसे अपनी माता मानते हैं इसलिए श्लोक में आया है कि माता भूमिः पुत्रो अहम पृथव्या - अर्थात भूमि हमारी माता है और मैं भूमि का पुत्र हूं इसलिए यह श्लोक मनीषियों को अपने जीवन में रेखांकित कर भूमि की सेवा और संरक्षण करना वर्तमान समय की मांग है क्योंकि इस भूमि से हमारी कृषि जुड़ी हुई है वैसे भी भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70 फ़ीसदी जनसंख्या कृषि परनिर्भर है इसलिए भूमि की रक्षा, सेवा, संरक्षण करना हर भारतीय का परम कर्तव्य है इसमें हम अन्नदाता द्वारा कृषि के रूप में किए गए यज्ञ में अपने सहयोग रूपी आहुति समझना हम आध्यात्मिक रूपी मनीषियों के लिए बेहतर होगा। बात अगर हम घटती कृषि भूमि,बढ़ते भूमि क्षरण, पड़ित भूमि, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण जैसे अनेक मुद्दों की करें तो हालांकि सरकार द्वारा इन्हें रेखांकित कर उस अनुरूप अपने रणनीतिक रोडमैप बनाकर क्रियान्वयन करने के क्रम पर कार्य शुरू है और कृषि मंत्रालय सहित अनेक संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय समय पर अनेक वेबीनार, अंतरराष्ट्रीय सम्मिट,सेमिनार कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं लेना इत्यादि क्रम किया जाता है परंतु हमें इस क्षेत्र के लिए तात्कालिक प्रौद्योगिकी की सेवाओं से जल, भूमि और मिट्टी को संरक्षित करने को रेखांकित करना होगा। साथियों बात अगर हम माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा एक कार्यक्रम में संबोधन की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने भी कहा, यह समझना होगा कि प्राकृतिक स्रोत जैसे जल, मिट्टी, भूमि अक्षय नहीं हैं, न ही इन्हें फिर से बनाया जा सकता है। मानव का भाग्य और भविष्य इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ही निर्भर है।वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में अधिकांश भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। देश के एक बड़े भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में मिट्टी सूख कर रेतीली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है।मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है।पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों, जैसे गोबर, गौ मूत्र आदि की सहायतासे न केवल कृषि को बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है। देशी खाद और कीटनाशक, पारंपरिक पद्धति से कम लागत में ही बनाए जाते हैं जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।समय के साथ, भूमि की पैदावार को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशकों आदि की खपत बढ़ती गई है। विगत दशकों में उर्वरक की खपत अस्सी गुना और कीटनाशकों का प्रयोग छह गुना बढ़ा है जिससे कृषि, भूमि क्षरण के दुष्चक्र में फंस गई है और किसान कर्ज़ के। हमारा दायित्व है कि अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ हम धरती माता का भी स्वास्थ्य सुनिश्चित करें। उसकी जैविक उर्वरता बनाए रखें।प्राकृतिक जैविक खेती ही इसका समाधान देती है। यह संतोष का विषय है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, आप जैसी संस्थाओं द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।सरकार द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य को बारह पैमानों पर मापने के लिए, सोइल हेल्थ कार्डस व्यापक पैमाने पर प्रचलित किए गए हैं। मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।कृषि हमारी समृद्धि और सम्मान का प्रतीक है। ऋग्वेद में कहा गया है -कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान-

कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करोमुझे विश्वास है कि प्राकृतिक खेती न सिर्फ हमारे किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगी बल्कि धरती माता को सम्मान और स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी।मानव समाज का निर्माण, कृषि के विकास के साथ जुड़ा है। हमारे पर्व, त्योहार, संस्कृति, संस्कार, सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहे हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है जीव जीवनम् कृषिः अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है।कृषि, हमारी संस्कृति, प्रकृति से अलग नहीं हो सकती।भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसेः पाराशर कृत कृषि पराशर, पाराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवनविनोद आदि। हमारे राष्ट्रीय गीत में भी वंदे मातरम् के रूप में धरती माता की वंदना की गई है। उसे सुजलाम सुफलाम अर्थात पावन जल और फल प्रदान करने वाली कहा गया है।

ऐसी धरती की संतान के रूप में, हम उसके स्वास्थ्य, उसके पोषण को कैसे नजरंदाज कर सकते हैं? कृत्रिम रसायन डाल कर, सालों तक उसका दोहन और शोषण कैसे कर सकते हैं! माता के प्रति यह निष्ठुरता, हमारे सनातन संस्कारों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि, हमारी संस्कृति, प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। उन्होंने कृषि अनुसंधान संस्थानों से, भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था पर लिखे गए प्रामाणिक ग्रंथों जैसे - पाराशर कृत कृषि पराशर, पाराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर कृत उपवन विनोद आदि पर शोध करने और किसानों को हमारी प्राचीन कृषि पद्धति से परिचित कराने का आग्रह किया। उन्होंने कृषि विश्विद्यालयों से अपेक्षा की कि वे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें तथा कृषि के क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें।इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि एक कालखंड था, जब देश में खाद्यान्न का संकट था, जिसके चलते रासायनिक खेती के साथ हरित क्रांति हुई लेकिन अब अलग स्थिति है। हमारा देश अधिकांश खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर एक या नंबर दो पर है और कृषि निर्यात भी बढ़ रहा है, जो सालाना चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बीच के कालखंड में भौतिकवादी सोच के परिणामस्वरूप भूमि के स्वास्थ्य की चिंता ओझल होती गई, लेकिन अब देश की आजादी के पचहत्तर साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर आवश्यक है कि भूमि के सुपोषण को कायम रखा जाएं।

भारत पहले सिंधु नदी के जल पर देश के वास्तविक नियंत्रण की तैयारी करे

अंजन रॉय

पानी में आसानी से आग लग सकती है। जब सिंधु नदी के जल की बात आती है, तो हम देख रहे हैं कि यह कितना ज्वलनशील हो सकता है - कम से कम अभी के लिए, मौखिक रूप से ही सही, विशेषकर भारत द्वारा सिंधु जलसंधि को निलंबित करने के बाद।

यह एक व्यापक सशस्त्र संघर्ष का केंद्र भी बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर विचार भी हैं। एक व्यापक या लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से बचना भारत के हित में है, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक वृद्धि पटरी से उतर सकती है। युद्ध से उच्च राजकोषीय घाटा, या आर्थिक नीति की बाध्यताओं से ध्यान भटकाना, विकास प्रक्रिया को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है।

भारत के लिए पाकिस्तान को दंडित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह देश को आर्थिक रूप से भूखा रखे और उसके अंतिम आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ाये, ताकि नागरिक जीवन पर सेना की पकड़ ढीली हो जाये। सिंधु जल संधि की बात करें तो जल संधि को स्थगित रखना अच्छी बात थी, लेकिन वास्तव में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। और यहीं कहानी की असली कहानी है।

अब ऐसी खबरें हैं कि भारत बगलिहार बांध का उपयोग करके चिनाब नदी के प्रवाह को रोकने का प्रस्ताव रखता है। चिनाब एक पश्चिमी नदी है और संधि के तहत भारत केवल कुछ सीमित तरीकों से इसका उपयोग कर सकता है। यह एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है, जिसका अर्थ है कि केवल सीमित उपयोग। बगलिहार में 900 मेगावाट क्षमता का पनबिजली स्टेशन है। लेकिन इसकी भंडारण क्षमता सीमित है। ट्रे को अलग रखना और इसके पानी को मोड़ना वास्तव में पाकिस्तान की नस को काटना हो सकता है। देश अपने अस्तित्व के लिए इन पानी के उपयोग पर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन यह निर्णय आतंकवादी राज्य को तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब पाकिस्तान में पानी का प्रवाह वास्तव में रुक जाये। इसका मतलब है कि भारत के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वास्तविक बुनियादी ढाँचा और साधन होने चाहिए।

सिंधु जल प्रणाली की पश्चिमी नदियाँ, साथ ही भारत से होकर बहने वाली पूर्वी नदियाँ, गर्मियों के महीनों में भारी मात्रा में पानी प्राप्त करती हैं, जब ग्लेशियर और हिमालय के ऊपरी हिस्से पर अधिक तापमान होने लगता है। हिमालय की पिघलती बर्फ नदियों में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ती है। भौगोलिक रूप से हिमालय को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शीतल जल भंडार माना जाता है, अन्य दो हैं दोनों ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका। सर्दियों के महीनों में गिरने वाली और जमने वाली बर्फ, उपमहाद्वीप में इन गर्म महीनों में पिघलने लगती है।

सिंधु जल प्रणाली में छह नदियाँ हैं, पूर्वी नदियाँ, ब्यास, सतलुज और रावी ये भारत की ओर जाती हैं। सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। पश्चिमी नदियों को पिघलते हिमालय से भारी मात्रा में पानी मिलता है।

लेकिन इन नदियों के ऊपरी इलाकों में पूरे मौसम में बढ़ते पानी को संग्रहित करने के लिए बहुत कम बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। उन्हें रोके रखने से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है और झरने के प्रवाह के विभिन्न स्तरों पर दबाव पड़ सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हाइड्रोलॉजिकल क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होगी।

जहां तक आम जानकारी है, वर्तमान में समग्र प्रवाह के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को संग्रहित करने के लिए ऐसा बहुत कम बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। 1960 के बाद से, हमने उच्च जल प्रवाह के मौसम में प्रवाह के कुछ हिस्सों को संग्रहित करने के लिए ऐसी कार्य योजना पर ज्यादा विचार नहीं किया है।

ऐसी कोई भी सुविचारित योजना बहुत बड़ा अंतर ला सकती थी। सिर्फ पाकिस्तान को दंडित करने के लिए नहीं, क्योंकि यह इस रणनीतिक सोच का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ये पानी उत्तरी भागों में कृषि और खेती की गतिविधियों के साथ-साथ घरों में अच्छे पेयजल की आपूर्ति के लिए भी बहुत बड़ा अंतर ला सकते थे।

अब, जब हम देख रहे हैं कि ये पानी क्या रणनीतिक हथियार हो सकते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम के लिए एक एकीकृत योजना के बारे में सोचने का समय आ गया है।

निकाय प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से की मुलाकात

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल सहित हरिद्वार मेयर एवं विभिन्न नगर पालिका अध्यक्षों ने मुलाकात की।

इस अवसर पर उक्त स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस विषय पर हर संभव उचित सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मेयर हरिद्वार विकास शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका डोईवाला नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका चमोली संदीप रावत, अध्यक्ष नगर पालिका हरबर्टपुर नीरू देवी, अध्यक्ष नगर पालिका मसूरी मीरा सकलानी मौजूद रहे।

सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू के नाम से होगी बद्रीनाथ में पूजा: महाराज

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोकनिर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने आपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि भारतीय सेना की इस बहादुरी और कौशल की कहानी ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाएं त्रिशूल हैं जिसने दुश्मन के घर में घूसकर उसे पहलगाम हमले का माकूल जवाब दिया है।

प्रदेश के पर्यटन, लोकनिर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पहले त्रेतायुग में हनुमान जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मन को घर में घूसकर मारा था और अब बालाकोट के बाद एक बार पुन: हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर सीमा पार बैठे आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया है।

पतंजलि विवि, रिसर्च फाउण्डेशन, भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग व शिक्षा मंत्रालय के मध्य एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

हरिद्वार (नवल टाइम्स)। भारत के प्राचीन गौरवमयी ज्ञान परम्परा के संरक्षण के लिए संकल्पित शोध संस्थान पतंजलि विश्वविद्यालय व पतंजलि रिसर्च फाउण्डेशन (पीआरएफ) एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य परस्पर सहयोग एवं शैक्षणिक समन्वय के लिए एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली की कार्यान्वयन समिति व एनएएसी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्त्रबुद्धि ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से आईकेएस प्रभाग के अंतर्गत विविध विषयों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, कार्यशाला व सम्मेलन आदि के आयोजन के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय को आईकेएस केंद्र के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। साथ ही पतंजलि विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध शोध संस्थान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली पर किए जा रहे विद्वत्तापूर्ण कार्यों के प्रकाशन और प्रसार के लिए एक संयुक्त परियोजना भी प्रारंभ की जा सकेगी।

कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय और पीआरएफ्री इस कार्य के निष्पादन में अपनी वैज्ञानिक जनशक्ति का प्रयोग करेंगे। आईकेएस प्रभाग भारतीय इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय की स्थापना पर पतंजलि विश्वविद्यालय, आईकेएस केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें न केवल पुरातात्विक कलाकृतियां शामिल होंगी, बल्कि ऐतिहासिक ज्ञान, वैज्ञानिक साक्ष्य और भारतीय ज्ञान प्रणाली का व्यापक प्रतिनिधित्व भी होगा। पतंजलि विश्वविद्यालय आईकेएस प्रभाग से पूर्व सहमति और अनुमोदन के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम या व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी विकसित करेगा इस अवसर पर प्रो. सहस्त्रबुद्धि ने कहा कि आईकेएस प्रभाग इतिहास, भारतीय दर्शन आदि के अनुशासन के भीतर भारतीय ज्ञान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित अनुसंधान में पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि आईकेएस प्रभाग पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इतिहास-केंद्रित वैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित करेगा, जिसमें भारतीय दर्शन, इतिहास और ज्ञान प्रणालियों के मूलभूत सिद्धांतों का पता लगाने और उनकी व्याख्या करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करेगा। साथ ही आईकेएस प्रभाग शोध कार्यों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ संपर्क में मदद करेगा।

कार्यक्रम में आईकेएस. प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक प्रो. जी. सूर्यनारायण मूर्ति, पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति डॉ. मयंक अग्रवाल, पतंजलि हर्बल रिसर्च डिविजन की प्रमुख डॉ. वेदप्रिया आर्या व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी एवं प्रगतिशील कृषकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

मातृशक्ति के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु संकल्पित होकर निरन्तर कार्य कर रही है प्रदेश सरकार : धामी

(नवल टाइम्स)

ऋषिकेश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने ऋषिकेश के आइडीपीएल मैदान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी एवं प्रगतिशील कृषकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इससे पहले उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, कृषि और उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए स्टाल्स का भी अवलोकन किया। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे।

इस संवाद कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की कई महिलाएं और प्रगतिशील कृषक मौजूद रहे। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने लखपति दीदी श्रीमती रीना रावत से संवाद किया। श्रीमती रीना स्वयं सहायता समूह चलती हैं और प्रदेश में चल रही लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं। संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने उनसे पूछा कि लखपति दीदी योजना ने कैसे उनके जीवन में बदलाव लाया है। इसके जवाब में श्रीमती रीना रावत ने कहा कि उनके समूह में 8 से दस महिलाएं हैं जो लखपति दीदी योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि आज वह फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। पहले उन्हें उनके पति के नाम से जाना जाता था लेकिन अब वह अपने नाम और काम से जानी और पहचानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके समूह में हर महिला दस से 15 हज़ार तक की आमदनी कर रही हैं।

हरिद्वार के प्रगतिशील किसान और मशरूम पालक श्री मनमोहन ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज से संवाद के दौरान बताया कि 2017 में उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर मशरूम उत्पादन शुरू किया और लोगों को रोज़गार भी दिया। श्री चौहान

ने श्री मनमोहन से पूछा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है किसानों की आमदनी दुगनी करना तो क्या आपकी आमदनी बढ़ी। इसके जवाब में किसान श्री मनमोहन ने उन्हें बताया कि आमदनी तो कई गुना बढ़ी हैं। बीते चार से पांच वर्षों में उन्होंने मशरूम उत्पादन में 12 से 15 करोड़ का व्यापर किया है। आज पूरे उत्तराखंड में वह मशरूम सप्लाई करते हैं और डोमिनोस जैसे बड़े ब्रांड्स भी उनसे व्यापर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके फार्म का नाम मामा भांजा फार्म हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिबराज चौहान ने लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों और किसानों को संबोधित भी क किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आ कर वह यहाँ के लोगों के सत्कार और मानसम्मान को देखकर अभिभूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग हैं तो वो उत्तराखंड में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी कि सरहाना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र/ मोदी के मार्गदर्शन और श्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति की और बढ़ रहा हैं। श्री चौहान ने राज्य की महिलाओं की सरहाना करते हुए कहा कि देवता वहीँ वास करते हैं जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है और उत्तराखंड की नारी यशस्वी और मेहनती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए सरकार संसद और विधानसभाओं महिलाओं को आरक्षण देगी। उन्होंने कहा की उत्तराखंड में सवा लाख बहनें लखपति दीदी बन गई हैं और ये सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सुदृढ़ करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री धामी को बधाई देते हुए कहा कि देश में जो बेहतरीन काम हो रहे हैं, उसमे उत्तराखंड भी शामिल हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालयाज के सरहाना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत कई बेहतरीन उत्पाद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन उत्पादों की और बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग और प्रचार प्रसार हो जाये तो ये उत्पाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध होंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि हाउस ऑफ हिमालयस के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तराखंड में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस खोलेगा ताकि हाउस ऑफ़ हिमालयाज का ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, रिसर्च में विकास व्यापक तौर पर हो सके।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि पहाड़ आबाद रहने चाहिए और ये संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा कि भारत सरकार ने इस योजना के लिए फिर से सर्वे करवाया हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आवास से वंचित न रह सके। सर्वे में ज्ञात हुआ हैं कि एक लाख 72 हज़ार लोगों के पास पक्के माकन नहीं हैं। इसके लिए आवास कि पात्रता में भी बदलाव किया गया है। अब 15 हज़ार तक की आय वालों और दुपहिया वहान मालिकों को भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत माकन दिए जायेंगे।

स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए: मुख्यमंत्री

- शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर किया जाए कार्य
- बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए
- प्रत्येक जनपद में प्रथम चरण में क्लस्टर विद्यालय में बनाये जायेंगे एक-एक आवासीय हॉस्टल

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का रजतोत्सव कैलेंडर बनाया जाए। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलस्टर विद्यालयों में आवासीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवासीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। पहले चरण में प्रत्येक जनपद में एक-एक आवासीय हॉस्टल बनाया जाए। 559 कलस्टर विद्यालयों के 15 किमी के अंतर्गत छात्र-छात्राओं की परिवहन व्यवस्था के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर साल बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें समय पर मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसके लिए सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। जनपद, मण्डल और राज्य स्तरीय कैडर में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए। स्कूलों में एनसीसी और एन.एस.एस को बढ़ावा दिया जाए, जिन स्कूलों में अभी इनकी सुविधा नहीं हैं, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का चयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सी.एस.आर फण्ड के तहत सहयोग के लिए अनुरोध भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्यों में तेजी लाई जाए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता के अनुसार पूर्ण उपलब्धता हो, इसके लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत, महानुभावों का उल्लेख, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, लोककथा, लोक साहित्य, संगीत और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा झरना कमठान, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल अरौर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविरों में होगी विभिन्न समुदायों की भागीदारी

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों एवं शिविरों में समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। विशेष रूप से मुस्लिम समाज के प्रतिभागियों की उल्लेखनीय उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि योग अब धर्म और समुदाय की सीमाओं से परे एक स्वास्थ्य और एकता का माध्यम बन चुका है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन, हरिद्वार के नोडल अधिकारी डॉ. अवनीश उपाध्याय ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में आयुर्वेद और योग के प्रति आमजन का रुझान तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहाकि हरिद्वार स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की ओर लोगों का विश्वास बढ़ा है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि यह समाज में भाईचारे, शांति और समरसता का संदेश भी देता है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सालियर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. नवीन दास ने जानकारी दी कि सालियर में प्रतिदिन आयोजित होने वाले योग शिविरों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी है।

योग शिविर में शामिल हुए प्रतिभागियों में से अकरम, शमीमा, कय्यूम और सफीना ने भी अपने अनुभव साझा किए। अकरम बताते हैं कि पहले मैं तनाव, थकावट और नींद की समस्या से परेशान था। योग करने के बाद अब मैं खुद को शांत, सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता हूं। योग ने मेरी दिनचर्या को संतुलित किया है और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाया है। कयूम का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है। वे कहते हैं कि योग से पहले मेरी दिनचर्या अनियमित थी और मैं जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था। अब मैं खुद को बेहतर ढंग से समझ पाया हूं। योग ने आत्मनियंत्रण, अनुशासन और मानसिक स्पष्टता दी है। इन सभी प्रतिभागियों के अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का भी आधार है।

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. स्वास्तिक सुरेश ने कहाकि योग न किसी धर्म से बंधा है और न ही किसी वर्ग से।

राज्य स्तरीय गन्ना सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी ने टेका श्री दरबार साहिब में मत्था

दरबार साहिब के सज्जादे गद्दी नशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज का लिया आशीर्वाद

देहरादून(नवल टाइम्स)। राज्य स्तरीय गन्ना सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवरी सैनी (राज्यमंत्री दर्जा) ने मंगलवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उन्होंने श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के साथ शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों के मध्य प्रदेश में किसान, किसानी और गन्ने की गुणवत्ता एवम् उत्पादकता से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्तवपूर्ण मुद्दों सहित प्रदेश के समसामयिक विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

श्री दरबार साहिब की परंपरा के अनुसार श्यामवीर सैनी का स्वागत किया गया। उन्होंने श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की उल्लेखनीय सेवाओं को विशेष रूप से रेखांकित किया और अस्पताल की ओर से आमजन को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवा में किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने श्री महंत देवेन्द्र दास जी महाराज को प्रदेश में गन्ने की नई किस्मों की उत्पादकता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गन्ने की विभिन्न प्रजातियों में लाल सड़न की समस्या आ रही थी, इसकी निजात के लिए वैज्ञानिक स्तर पर निराकरण किए गए हैं। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज़ की ओर से जैविक खेती से जुड़े कई प्रोजेक्टों पर कार्य किया जा रहा है। किसानों को जैविक खेती से होने वाले दीर्घकालिक लाभों के बारे में भी बातचीत हई।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

देहरादून। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा व क्षमता के आधार पर मिल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं को निष्पक्षता व ईमानदारी से संपन्न कराया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि साढ़े तीन वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब तेईस हजार के आंकड़े को पार करने वाली है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 52 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के 18 प्रोफेसर्स व 36 एसोसिएट प्रोफेसर और नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर व मेडिकल सोशल वर्कर के 33 पदों पर चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ संपन्न कराने के लिए कड़े प्राविधान किए हैं। पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया गया है। जिसके चलते युवाओं को उनकी योग्यता व प्रतिभा का पूरा सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिभा व परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस सफलता में उनके अभिभावकों व गुरुजनों के योगदान व मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अध्यापन अधिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिसके माध्यम से हम युवाओं का मार्गदर्शन कर उनका भविष्य ही नहीं गढ़ते हैं बल्कि समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को इस चुनौतीपूर्ण दायित्व को पूरी ईमानदारी व समर्पण से निभाने के लिए प्रतिबद्धता से जुटना होगा। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी नौकरी ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा करने का महान अवसर है। लिहाजा आपके कार्य व्यवहार में हमेशा सेवा की भावना परिलक्षित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने, नए अस्पतालों का निर्माण व आधुनिकीकरण करने के साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए भी ठोस कार्य हो रहे हैं। देश में सबसे पहले उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जा रहे हैं।

कानूनी सलाहकार
एड. अनुज कुमार शर्मा
चैम्बर नं. 20, रोशनाबाद
हरिद्वार (उत्तराखंड)
मो. 9837387718

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजीव शर्मा ने किरण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, निकट गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) से छपवाकर, म.नं. डी-31/2 आदर्शनगर कालोनी, गोल गुरूद्वारा, सेंटमेरी स्कूल के पीछे, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड) से प्रकाशित किया।

: सम्पादक :
संजीव शर्मा
मो. 8057605991/9897106991
ईमेल: navaltimes@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा

प्रबंध संपादक
डा. संदीप भारद्वाज
बिजनौर प्रभारी
विशाल शर्मा

सभी पद अवैतनिक हैं